(1) यह अधिनियम भारत के असाधारण राजपत्र में अधिसूचित किया गया है।

(2) भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों/विभागों के मंत्रियों से इस अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध किया गया है।

(3) राज्य सरकार के मुख्य सचिवों से पर्याप्त बजट संबंधी प्रावधानों सहित अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक कार्रवाई शुरु करने के लिए अनुरोध किया गया है।

(4) दृष्टि विकलांग व्यक्तियों के लाभ के लिए इस अधिनियम की टाकिंगइबुक तैयार की गई है।

(5) विकलांगों के पुनर्वासन में लगे हुए 400 से अधिक गैर सरकारी संगठनों को इस अधिनियम की एक प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए भेजी गई है।

(6) इस अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा तथा मानीटरिंग करने के लिए "विकलांग व्यक्ति मुख्य आयुक्त" के पद का सृजन किया जा रहा है।

इस्पात उत्पादन में गैर-सरकारी निवेश

477. **श्री चिमनभाई हरिभाई शुक्ल:** क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किन-किन राज्यों में गैर-सरकारी और सरकारी क्षेत्र द्वारा इस्पात परियोजनाएं लागू की जा रही हैं/लागू की जाने वाली हैं और उनकी संख्या क्या है; और

(ख) वर्ष 1996-97 के दौरान कितनी नई परियोजनाओं को स्वीकृति देने का विचार है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव): (क) और (ख) लोहा और इस्पात उद्योग को स्थान-स्थिति संबंधी कतिपय शर्तों पर अनिवार्य लाइसेंसिंग के प्रतिबन्ध से मुक्त कर दिया गया है। उद्यमी अपने वाणिज्यिक निर्णयों के आधार पर निवेश करने के संबंध में स्वयं निर्णय ले सकते हैं। उपलब्ध सूचना के अनुसार अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों द्वारा स्वीकृत 15 इस्पात परियोजनाएं निजी क्षेत्र में कार्यान्वित की जा रही हैं/की जाएंगी। इस समय सरकारी क्षेत्र की किसी नई इस्पात परियोजना पर विचार नहीं किया जा रहा है। इन 15 संयंत्रों का राज्यवार ब्यौरा निम्नानुसार है:—

आंध्र प्रदेश	2	गुजरात	1
कर्नाटक	3	महाराष्ट्र	4
मध्य प्रदेश	3	तमिलनाडु	1
उत्तर प्रदेश	1		

Benefits generated from Rural Employment Schemes

478. SHRI G.G. SWELL:
SHRI CHIMANBHAI MEHTA:

Will the Minister of RURAL AREAS AND EMPLOYMENT be pleased tostate:

(a) whether it is a fact that rural employment schemes have not generated commensurating benefits in proportion to amount spent on the schemes; and

(b) the nature and size of unemployment at present in rural areas?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL AREAS AND EMPLOYMENT (DEPARTMENT OF RURAL EMPLOYMENT AND POVERTY ALLEVIATIOIN) (SHRI VILAS BABURAO MUTTEMWAR): (a) and (b) No, Sir. Rural Wage Employment Programmes such as the Jawahar Rozgar Yojana and the Employment Assurance Scheme have been successful in generating employment in the rural areas. Under these two programmes 1225.66 million mandays of employment was generated during the year 1994-95 corresponding to which an expenditure of Rs. 5503.78 crores was incurred. During the current year (1995-96) 694.44 million mandays of employment has been generated under these two schemes (as on December 31, 1995) against which an expenditure of Rs. 3415.85 crores has been incurred. It may be mentioned that these schemes are targeted at the rural poor who are below the poverty line, a large majority of whom are landless labourers. Due to seasonal factors affecting the agricultural

sector, the demand for wage employment generally increases during the lean agricultural season. In this regard, the Planning Commission have estimated that the total unemployment in the country at the end of March, 1995 was of the order of 18.69 million. However, separate break-up for rural and urban areas is not available. Further the Planning Commission has stated that according to 43rd round NSS (1987-88) the total unemployment was 14.35 million of which 66.78% was in rural areas.

राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन

479. **श्री दिलीप सिंह जूदेव:** क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1991-92 से 1994-95 के दौरान प्रति वर्ष, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन एवं त्वरित जल प्रदाय कार्यक्रमों के अंतर्गत राज्य-वार और वर्ष-वार कितनी राशि जारी की गई;

(ख) इन राशियों में से राज्यवार कितनी राशि व्यय की गयी;

(ग) इन योजनाओं के अंतर्गत राज्य-वार कितने-कितने नल कूप और हैंडपंप स्थापित किए गए तथा हैंड पंप स्थापना के अलावा अन्य किन कार्यों पर कितनी राशि व्यय की गई; और

(घ) इन वर्षों के दौरान भूगर्भ जल स्रोतों एवं परंपरागत पेयजल स्रोतों की सुरक्षा तथा विकासात्मक प्रयोजनों पर व्यय की गई राशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल): (क) और (ख) 1991-92 से 1994-95 तक ए०आर०डब्ल्यू एस०पी० सहित राजीव गांधी राष्ट्रीय पेय जल मिशन के अन्तर्गत राज्य-वार जारी की गई धनराशियां और किया गया खर्च अनुपत्र में दिया गया है [देखिए परिशिष्ट 176, अनुपत्र संख्या 29] न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत धनराशियां संबंधित राज्य सरकारों द्वारा जारी की जाती हैं। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य-वार खर्च अनुपत्र में दिया गया है। [देखिए परिशिष्ट 176, अनुपत्र संख्या 29]

(ग) और (घ) इस प्रकार की जानकारी को केन्द्रीय सरकार के स्तर पर मानीटर नहीं किया जाता है।

Sponge Iron Manufacturers' Association

480. SHRI V. RAJAN CHELLAPPA: Will the Minister of STEEL be pleased to state:

(a) whether the Sponge Iron Manufacturers' Association has urged for reduction of customs duty on iron ore; and

(b) if so, the details thereof and the reaction of government thereto?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF STEEL (SHRI SONTOSH MOHAN DEV): (a) Yes, Sir.

(b) Representations received from the domestic steel producers/associations regarding change in customs duty are considered and remedial measures taken by Government wherever necessary.

Investment in Rural Development Sectors

481. SHRI NILOTPAL BASU: Will the Minister of RURAL AREAS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) the total investment in the rural development sector during the 8th Plan;

(b) the investment in the IRDP during the same period;

(c) the percentage of families assisted under the IRDP which have overcome the poverty threshold during each of five years on the basis of the results of the concurrent evaluation; and

(d) the corresponding figure at the start of the Plan period?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL AREAS AND